उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार सर्वप्रथम स्थायी रिक्त पद भरे जाते हैं, अतः अपर न्यायाधीशों के उक्त पद रिक्त हैं यद्यपि अक्तूबर, 1984 से स्थायी न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।

(ख) और (ग) न्यायाधीशों का चयन, सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करके किया जाता है जो एक निरन्तर प्रक्रिया है। सरकार, न्यायाधीशों के रिक्त पदों के शीघ्र भरे जाने का हर संभव प्रयास कर रही है। अतः यह बताना संभव नहीं है कि ये रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश

1173. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस समय कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) इनमें से अल्पसंख्यक समुदायों के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) तारीख 1—8—88 को उपलब्ध अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)।

(ख) उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

उच्च न्यायालय	1—8—1988 को
1. इलाहाबाद	48
2. आंध्र प्रदेश	19
3. मुम्बई	43
4. कलकत्ता	38
5. दिल्ली	22
6. गुवाहाटी	9
7. गुजरात	16
8. हिमाचल प्रदेश	4
9. जम्मू-कश्मीर	7
10. कर्नाटक	22
11. केरल	20
12. मध्य प्रदेश	26
13. मद्रास	17
14. उड़ीसा	10
15. पटना	28
16. पंजाब और हरियाणा	23
17. राजस्थान	23
18. सिक्किम	2

Closing of CSIR Laboratory at Bhopal

1174. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to close down the Regional Research Laboratory of the CSIR at Bhopal;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any action is being taken to provide employment to the affected staff members and scientists?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) No, Sir. The CSIR Society has directed CSIR to explore the possibility of taking over of the Regional Research Laboratory (RRL), Bhopal, by the Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) or some other Public Sector Undertaking.

(b) and (c) Do not arise.